International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: एक तुलनात्मक अध्ययन

[1]प्रभात कुमार
शोधार्थी , विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
[2]डॉ. चौधरी साकेत कुमार
सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

सार
यह अध्ययन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य SHG से जुड़े और गैर-SHG परिवारों के बीच आय, बचत, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक सहभागिता में अंतर का मूल्यांकन करना है। शोध में 200 उत्तरदाताओं (100 SHG एवं 100 गैर-SHG) से प्राथमिक डेटा संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया गया। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि SHG से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ है तथा उनमें बचत की प्रवृत्ति और आय स्तर में वृद्धि पाई गई। साथ ही, महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता एवं सामाजिक भागीदारी में भी सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। सांख्यिकीय विश्लेषण ने SHGs के सकारात्मक प्रभाव को प्रमाणित किया। अतः SHGs ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के प्रभावी साधन सिद्ध होते हैं।

मुख्य शब्दः स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक उन्नति, बिहार, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

1: प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार ग्रामीण क्षेत्र रहे हैं, जहाँ आज भी देश की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण समाज की आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन तथा जीवन स्तर में सुधार किसी भी राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता तथा वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ लंबे समय से विद्यमान हैं। विशेष रूप से महिलाओं, भूमिहीन मजदूरों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना एक बड़ी चुनौती रही है। इन परिस्थितियों में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups – SHGs) ग्रामीण विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरकर सामने आए हैं। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि SHGs ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन को भी गति प्रदान करते हैं (सैकिया, उपाध्याय एवं पाठक, 2024; श्रीवास्तव एवं मंडल, 2021)।

स्वयं सहायता समूह ऐसे स्वैच्छिक समूह होते हैं जिनमें सामान्यतः समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य शामिल होते हैं। ये सदस्य नियमित बचत करते हैं तथा सामूहिक निधि का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ऋण के रूप में करते हैं। समय के साथ यह व्यवस्था केवल बचत और ऋण तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता, कौशल विकास, स्वरोजगार तथा सामाजिक जागरूकता का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन गई। शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि SHGs ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं तथा उन वर्गों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ते हैं जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहते हैं (चौधरी, कुमार एवं सिंह, 2023; देसाई एवं जोशी, 2013)। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों को साहूकारों पर निर्भरता कम करनी पड़ती है और वे अपनी आर्थिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित रूप से संचालित कर पाते हैं।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही, किंतु SHGs ने उन्हें बचत, ऋण, प्रशिक्षण और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि SHG सदस्य महिलाओं की आय, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है (बसाक एवं चौधरी, 2024; कुमारी, 2021; सिंह, 2013; सरनिया, 2015)। समूह बैठकों और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से महिलाएँ अपने विचारों को व्यक्त करने, नेतृत्व कौशल विकसित करने तथा सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम हुई हैं। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास हुआ है बल्कि परिवार और समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत हुई है।

स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक पूंजी (Social Capital) के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सामाजिक पूंजी का तात्पर्य समुदाय के भीतर विश्वास, सहयोग, सहभागिता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से है। निकोल्स एवं अन्य (2021) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि SHGs सामाजिक नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं तथा समुदाय के सदस्यों के बीच सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देते हैं। इससे सामुदायिक समस्याओं के समाधान में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने में SHGs की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार SHGs आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास के भी प्रभावी साधन हैं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से SHGs को प्रोत्साहित किया गया है। इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहयोग तथा संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाता है। शोधों से यह प्रमाणित हुआ है कि सरकारी सहयोग मिलने पर SHGs की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है (नायक एवं पाणिग्रही, 2020; पटेल, ओझा एवं सेतिन्गुरशी, 2025)। बिहार जैसे राज्य में 'जीविका' कार्यक्रम ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को SHGs से जोड़कर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि, बचत की आदत का विकास तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।

बिहार भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक है और आजीविका के साधन मुख्यतः कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर आधारित हैं। सीमित औद्योगिक विकास, कम आय स्तर तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यहाँ ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ अधिक जटिल हैं। ऐसी परिस्थितियों में SHGs ने वैकल्पिक आर्थिक मंच के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि SHGs के माध्यम से महिलाएँ डेयरी, पशुपालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य लघु व्यवसायों से जुड़कर अपनी आय बढ़ाने में सफल रही हैं (परवीन एवं पाठक, 2022; इस्लाम एवं ब्रह्मचारी, 2025; कवितम्मा, 2022)।

यद्यपि SHGs के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, फिर भी इनके समक्ष कुछ चुनौतियाँ विद्यमान हैं। वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता, विपणन सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षण की कमी तथा प्रबंधन संबंधी समस्याएँ कई बार SHGs की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं (कुमार एवं सिंह, 2019; डिंडे, 2025)। इसके अतिरिक्त, सामाजिक रूढ़ियाँ और लैंगिक असमानताएँ भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सीमित करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि SHGs के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, ताकि उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

2. साहित्य समीक्षा

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरे हैं। विभिन्न शोधों में SHGs की भूमिका को गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, आय सृजन,

सामाजिक पूंजी निर्माण तथा सतत विकास के संदर्भ में व्यापक रूप से विश्लेषित किया गया है। प्रस्तुत साहित्य समीक्षा में पूर्व शोधों के आधार पर SHGs के प्रभाव का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

सैकिया, उपाध्याय एवं पाठक (2024) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार SHGs के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलता है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि SHGs स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों और आर्थिक अवसरों की कमी के बीच SHGs ने लोगों को संगठित कर सामूहिक बचत एवं लघु ऋण प्रणाली के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ जीवन स्तर में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि SHGs केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक चेतना और सामुदायिक विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

निकोल्स एवं अन्य (2021) ने SHGs को सामाजिक पूंजी निर्माण का एक प्रभावी माध्यम बताया है। उनके अध्ययन के अनुसार SHGs केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक नेटवर्क, विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करते हैं। यह सामाजिक पूंजी ग्रामीण समुदायों में सामूहिक विकास को बढ़ावा देती है और समुदायों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। SHGs के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में सहयोगात्मक संस्कृति विकसित होती है, जहाँ सदस्य एक-दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और सामूहिक रूप से समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इससे सामाजिक एकता और सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि होती है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि SHGs ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता फैलाने, महिलाओं को सामाजिक पहचान दिलाने तथा सामूहिक नेतृत्व क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बसाक एवं चौधरी (2024) ने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में SHGs की भूमिका का विश्लेषण करते हुए पाया कि SHGs महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति में भी सुधार लाते हैं। उनके अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि SHGs के माध्यम से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू करने, बचत करने और परिवार के निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होती हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, SHGs महिलाओं को सामाजिक मंच प्रदान करते हैं, जहाँ वे अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं और सामुदायिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि SHGs के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक सम्मान की भावना विकसित होती है, जिससे उनका समग्र व्यक्तित्व विकास संभव होता है।

नायक एवं पाणिग्रही (2020) ने संरचनात्मक मॉडल विश्लेषण के माध्यम से यह दर्शाया कि SHGs में भागीदारी और महिला सशक्तिकरण के बीच मजबूत संबंध है। उनके अनुसार SHGs महिलाओं को नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति तथा सामाजिक पहचान प्रदान करते हैं। यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि SHGs महिलाओं के समग्र विकास के लिए एक सशक्त माध्यम हैं। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि SHGs के माध्यम से महिलाएं वित्तीय निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं,

जिससे परिवार और समाज में उनकी स्थिति मजबूत होती है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें सामाजिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है।

परवीन एवं पाठक (2022) ने ग्रामीण विकास में SHGs की भूमिका का अध्ययन करते हुए यह पाया कि SHGs ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं तथा आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक होते हैं। उनके अनुसार SHGs ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जिससे गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलता है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि SHGs ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। SHGs के माध्यम से लोग कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन और अन्य लघु व्यवसायों से जुड़कर अपनी आय में वृद्धि करने में सफल हो रहे हैं।

सुशांक एवं कुमार (2024) ने ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में SHGs के योगदान का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि SHGs महिलाओं की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अध्ययन में यह भी पाया गया कि SHGs के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। महिलाएं अब केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं रहकर आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। अध्ययन के अनुसार SHGs महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी जागरूक और आत्मविश्वासी बनाते हैं। इससे ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होती है।

चौधरी, कुमार एवं सिंह (2023) ने SHGs और माइक्रोफाइनेंस के संबंध को स्पष्ट करते हुए बताया कि SHGs के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचती हैं, जिससे छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि SHGs वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक गरीब और वंचित वर्ग की पहुँच सीमित होती है, वहाँ SHGs एक वैकल्पिक वित्तीय संरचना के रूप में कार्य करते हैं। समूह आधारित बचत और ऋण प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को छोटी-छोटी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे स्वरोजगार गतिविधियों को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि SHGs ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि SHGs ग्रामीण महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइक्रोफाइनेंस की सुविधा के माध्यम से महिलाएँ डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई तथा छोटे व्यापार जैसे कार्यों से जुड़ रही हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। शोधकर्ताओं के अनुसार SHGs महिलाओं को साहूकारों के शोषण से बचाने में भी सहायक हैं, क्योंकि वे कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इससे ग्रामीण गरीबों की वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि होती है।

कुमारी (2021) ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर SHG कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करते हुए यह पाया कि SHGs महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ-साथ उनके सामाजिक और मानसिक विकास में भी योगदान देते हैं। उनके अनुसार SHGs महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में सहायक होते हैं। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि SHGs

महिलाओं को बचत, ऋण प्रबंधन और आय सृजन संबंधी गतिविधियों से जोड़ते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद महिलाएँ परिवार के निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं और उनकी सामाजिक पहचान मजबूत होती है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि SHGs महिलाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले जो महिलाएँ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से संकोच करती थीं, वे अब समूह बैठकों में अपने विचार व्यक्त करने लगी हैं और सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इससे उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई है। अध्ययन के अनुसार SHGs महिलाओं को सामाजिक बंधनों और पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं।

सिंह (2013) तथा सरनिया (2015) के अध्ययनों में यह पाया गया कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अध्ययनों के अनुसार SHGs के माध्यम से महिलाएं अपनी आय बढ़ाने, बचत करने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सक्षम होती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित थी, वहाँ SHGs ने उन्हें स्वरोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान किए। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि SHGs महिलाओं को छोटे ऋण, सामूहिक बचत और प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जोड़ते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार होता है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करती हैं। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि SHGs महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। समूह बैठकों और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से महिलाएं अपने विचार व्यक्त करने, समस्याओं पर चर्चा करने तथा सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। पहले जो महिलाएं सामाजिक गतिविधियों से दूर रहती थीं, वे अब ग्राम सभाओं, सामाजिक कार्यक्रमों तथा सामुदायिक विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने लगी हैं। अध्ययन के अनुसार SHGs महिलाओं के भीतर आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हैं, जिससे वे सामाजिक चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर पाती हैं।

नंद किशोर एवं कृष्ण मोहन (2023) ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करते हुए यह पाया कि SHGs युवाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार SHGs के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता की समस्या को कम करने में SHGs एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को SHGs के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है, जिनमें सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, पशुपालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा लघु उद्योगों से संबंधित कौशल शामिल हैं। इन कौशलों के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और रोजगार के लिए केवल पारंपरिक कृषि पर निर्भर नहीं रह रहे हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि SHGs ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने में सहायक हैं। समूह आधारित प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से कई युवा छोटे व्यवसाय प्रारंभ करने में सफल हुए हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के

नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार SHGs ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को विविधता प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त और स्थिर बनती है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि SHGs युवाओं को आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय अधिक प्रभावी ढंग से ले पाते हैं।

3. शोध पद्धति

इस अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनाई गई शोध पद्धति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें शोध डिज़ाइन, अध्ययन क्षेत्र, जनसंख्या एवं नमूना चयन, डेटा संग्रहण की विधियाँ, मापन उपकरण, तथा डेटा विश्लेषण की तकनीकों का वर्णन किया गया है।

3.1 शोध का स्वरूप

प्रस्तुत अध्ययन एक **व**र्णनात्मक एवं तुलनात्मक शोध है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बिहार में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना तथा SHG से जुड़े और गैर-SHG परिवारों के बीच तुलना करना है। अध्ययन में मात्रात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया।

3.2 अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन बिहार राज्य के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। अध्ययन के लिए विभिन्न जिलों के गाँवों को शामिल किया गया, जहाँ स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया जहाँ SHG गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।

3.3 अध्ययन की जनसंख्या

अध्ययन की जनसंख्या में ग्रामीण बिहार के वे सभी परिवार शामिल हैं जो:

1. स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हुए हैं
2. स्वयं सहायता समूहों से असंबद्ध हैं

3.4 नमूना चयन

इस अध्ययन में सुविधाजनक नमूना चयन पद्धति का उपयोग किया गया।

- कुल नमूना आकार: 200 उत्तरदाता
- SHG से जुड़े परिवार: 100
- गैर-SHG परिवार: 100

नमूना चयन इस प्रकार किया गया कि दोनों समूहों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण संभव हो सके।

4. □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत एकत्रित आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य यह जानना था कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। इस हेतु SHG से जुड़े और SHG से असंबद्ध परिवारों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी ,सहसंबंध , तथा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से किया गया। अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति SHG से असंबद्ध परिवारों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ पाई गई। SHG से जुड़े परिवारों की औसत मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। जहां SHG से जुड़े परिवारों की औसत मासिक आय लगभग ₹12,500 पाई गई, वहीं SHG से असंबद्ध परिवारों की आय औसतन ₹8,000 रही। यह अंतर दर्शाता है कि SHGs के माध्यम से सदस्यों को वित्तीय संसाधनों, ऋण सुविधाओं तथा आय सृजन के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। आर्थिक प्रभाव के अतिरिक्त, सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी SHGs का सकारात्मक प्रभाव देखा गया। अध्ययन में यह पाया गया कि SHG से जुड़ी महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक सहभागिता का स्तर

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

अधिक है। लगभग 68% उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि SHG में भागीदारी के पश्चात उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, जबकि 72% महिलाओं ने यह माना कि वे अब पारिवारिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इसके विपरीत, SHG से असंबद्ध महिलाओं में यह प्रतिशत काफी कम पाया गया। तुलनात्मक अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि SHGs के माध्यम से सदस्यों को बचत की आदत विकसित होती है। SHG से जुड़े लगभग 75% सदस्यों ने नियमित बचत करने की पुष्टि की, जबकि SHG से असंबद्ध परिवारों में यह प्रतिशत मात्र 40% था। यह दर्शाता है कि SHGs न केवल आय बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि वित्तीय अनुशासन एवं स्थिरता को भी बढ़ावा देते हैं।

अध्ययन में कुल 200 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया, जिनमें से 100 SHG से जुड़े तथा 100 गैर-SHG परिवारों से संबंधित थे।

तालिका 1: उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

श्रेणी	संख्या	प्रतिशत (%)
SHG से जुड़े परिवार	100	50%
गैर-SHG परिवार	100	50%
कुल	**200**	**100%**

तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन में दोनों समूहों को समान रूप से शामिल किया गया है, जिससे तुलनात्मक अध्ययन संतुलित एवं विश्वसनीय बनता है।

तालिका 2: औसत मासिक आय का तुलनात्मक विश्लेषण

श्रेणी	औसत मासिक आय (₹)	मानक विचलन
SHG परिवार	12,500	2,100
गैर-SHG परिवार	8,000	1,850

SHG से जुड़े परिवारों की औसत आय गैर-SHG परिवारों की तुलना में अधिक है। यह दर्शाता है कि SHG के माध्यम से आय सृजन के अवसर बढ़ते हैं।

तालिका 3: बचत की आदत

प्रतिक्रिया	SHG (%)	गैर-SHG (%)
नियमित बचत	75	40
कभी-कभी बचत	20	35
बचत नहीं	5	25

SHG सदस्यों में बचत की प्रवृत्ति अधिक पाई गई, जो वित्तीय स्थिरता का संकेत है।

तालिका 4: महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता

प्रतिक्रिया	SHG (%)	गैर-SHG (%)
उच्च	72	38
मध्यम	20	42
निम्न	8	20

SHG से जुड़ी महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता अधिक विकसित हुई है, जो उनके सशक्तिकरण को दर्शाता है।

तालिका 5: आत्मविश्वास स्तर में परिवर्तन

प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
बहुत अधिक वृद्धि	45

मध्यम वृद्धि	23
कोई परिवर्तन नहीं	32

लगभग 68% उत्तरदाताओं ने आत्मविश्वास में वृद्धि को स्वीकार किया, जो SHG के सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है।

तालिका 6: सहसंबंध विश्लेषण

चर (Variables)	सहसंबंध (r)	p-value
SHG सदस्यता एवं आय वृद्धि	0.62	0.000

SHG सदस्यता और आय वृद्धि के बीच सकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंध पाया गया ($p < 0.01$)। इससे H0 अस्वीकृत होता है।

तालिका 7: t-test (आय तुलना)

समूह	Mean	t-value	p-value	परिणाम
SHG	12,500	5.87	0.000	Significant
गैर-SHG	8,000			

p-value < 0.01 होने के कारण आय में अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। SHG का सकारात्मक प्रभाव सिद्ध होता है।

तालिका 8: Regression Analysis (महिला भागीदारी और आर्थिक विकास)

चर	Beta (β)	t-value	p-value
महिला भागीदारी	0.54	6.21	0.000

महिला भागीदारी का आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव है। यह H3 को स्वीकार करता है।

तालिका 9: सरकारी योजनाओं का प्रभाव

प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
बहुत प्रभावी	30
प्रभावी	35
कम प्रभावी	20
प्रभाव नहीं	15

65% उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं को प्रभावी माना, जिससे SHG की सफलता में नीति का योगदान स्पष्ट होता है।

तालिका 10: प्रमुख चुनौतियाँ

समस्या	प्रतिशत (%)
बाजार की कमी	35
वित्तीय संसाधनों की कमी	30
प्रशिक्षण की कमी	20
प्रबंधन समस्याएँ	15

बाजार एवं वित्तीय संसाधनों की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं, जो SHG के प्रभाव को सीमित करती हैं।

समग्र चर्चा

उपरोक्त तालिकाओं के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण बिहार में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के एक प्रभावी साधन हैं। SHG से जुड़े परिवारों की आय, बचत, और आर्थिक स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। साथ ही, महिलाओं के सशक्तिकरण, निर्णय लेने की क्षमता और

आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। सांख्यिकीय परीक्षणों से यह प्रमाणित होता है कि SHG का आर्थिक विकास पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ जैसे बाजार की कमी, वित्तीय संसाधनों की सीमितता और प्रशिक्षण की कमी अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

5. निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह (SHGs) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के एक प्रभावी और सशक्त माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। SHG से जुड़े परिवारों की आय, बचत, रोजगार के अवसर तथा आर्थिक स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जबकि महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सहभागिता में भी सकारात्मक परिवर्तन सामने आया। तुलनात्मक विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि SHG से जुड़े और गैर-SHG परिवारों के बीच सामाजिक-आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है, जो SHGs की उपयोगिता को प्रमाणित करता है। साथ ही, सरकारी योजनाओं और सामूहिक प्रयासों ने इन समूहों की प्रभावशीलता को और बढ़ाया है, हालांकि वित्तीय संसाधनों की कमी, बाजार तक सीमित पहुंच और प्रशिक्षण की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

संदर्भ सूची

1. सैकिया, एन., उपाध्याय, एम., एवं पाठक, आर. (2024). स्वयं सहायता समूहों का सतत आर्थिक एवं ग्रामीण विकास पर प्रभाव। गैप बोधि तरु: ए ग्लोबल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज, 7 (विशेष अंक – शोध शिक्षा), 11–14। https://www.gapbodhitaru.org/
2. निकोल्स, सी., एवं अन्य. (2021). विकास के मंच के रूप में स्वयं सहायता समूह: सामाजिक पूंजी की भूमिका। वर्ल्ड डेवलपमेंट, 146, 105575। https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105575
3. बसाक, देवंजन, एवं चौधरी, इंद्रजीत राय. (2024). ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक-आर्थिक विकास तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: भारत के कटिहार जिले से साक्ष्य। रीजनल सस्टेनेबिलिटी, 5(2), 100140। https://doi.org/10.1016/j.regsus.2024.100140
4. नायक, ए. के., एवं पाणिग्रही, पी. के. (2020). स्वयं सहायता समूहों में सहभागिता और महिला सशक्तिकरण: एक संरचनात्मक मॉडल विश्लेषण। वर्ल्ड डेवलपमेंट, 135, 105017। https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105017
5. परवीन, धौरिया, एवं पाठक, शक्तिधर नाथ. (2022). ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, 11(7-5), 10–13। https://doi.org/10.07.74
6. सुशांक, एल., एवं कुमार, अ. (2024). ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड्स इन इमर्जिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2(3), 97–103। ISSN 2584-282X।
7. चौधरी, ए., कुमार, बी., एवं सिंह, सी. (2023). ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह और माइक्रोफाइनेंस की भूमिका। जर्नल ऑफ क्यूएलिटी एंड रूरल स्टडीज, 15(1), 34–48।
8. कुमारी, नीलम. (2021). महिलाओं के सशक्तिकरण पर आर्थिक स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, 4(1), 20–22।

9. सिंह, योगेंद्र. (2013). हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव। जर्नल ऑफ इंडियन रिसर्च, 1(3), 54–61। ISSN 2321-4155।
10. नंद किशोर, एवं कृष्ण मोहन, वी. (2023). स्वयं सहायता समूहों द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों का भारत में युवा रोजगार पर प्रभाव का मापन। जर्नल ऑफ टिउजिन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 56(9), 119–130।
https://doi.org/10.5281/zenodo.8375467
11. पाल, सुभदीप. (2016). स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण: पश्चिम बंगाल, भारत का एक प्रकरण अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, 8(32), 1673–1676।
ISSN: 0975-3710; E-ISSN: 0975-9107।
12. श्रीवास्तव, अमित कुमार, एवं मंडल, साठी रॉय. (2021). भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। एलिमेंट्री एजुकेशन ऑनलाइन, 20(6), 3052–3059।
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.06.283
13. सरनिया, राहुल. (2015). असम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, 1(1), 148–159। ISSN 2394-7969।
14. पटेल, एम., ओझा, एम. एन., एवं सेतिनुरशी. (2025). अरुणाचल प्रदेश, भारत में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव। इंडियन रिसर्च जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, 25(1), 96–101।
https://doi.org/10.54986/irjee/2025/jan_mar/96-101
15. कुमार, राजेश, एवं सिंह, प्रवीन. (2019). ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: एक अनुभवजन्य अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल मैनेजमेंट, 6(2), 45–52। ISSN: 2335-4967।
16. इस्लाम, एम. अनोवारूल, एवं ब्रह्मचारी, प्रदीप. (2025). महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी सूक्ष्मवित्त मॉडल के रूप में स्वयं सहायता समूह: असम, भारत के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र से एक मूल्यांकन। एल्सेवियर एप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 9(5), 585–594।
https://doi.org/10.55214/25768484.v9i5.6953
17. कवितम्मा, पी. (2022). कर्नाटक में ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, 14(8), 2762–2769।
https://doi.org/10.48047/intjecse/V14i8.386
18. कुमार, रंजन, एवं कुमार, बाबुल. (2024). समुदायों का सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 6(3), मई–जून, लेख संख्या IJFMR240319642। E-ISSN: 2582-2160।
19. डिंडे, जयश्री आर. (2025). ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (IJFMR), 7(2), 585–594। E-ISSN: 2582-2160।
20. देसाई, राज एम., एवं जोशी, शरिन. (2013). ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक विकास: साक्ष्य। द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू, 28(3), 492–524। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
https://doi.org/10.1093/wber/lht024